भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-549
दिनांक 04 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ

549. श्रीमती संगीता यादवः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने पशुपालन, डेयरी उत्पादन, मत्स्यपालन और पशुधन प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की संभावना तलाशने के लिए विदेशी सरकारों या उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बाsतचीत की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत के पशुपालन और डेयरी विधान, सेवाओं और क्षेत्रीय अभिशासन को आधुनिक बनाने के लिए कौन-कौन से सुधार किए गए हैं;

(ग) क्या पशुधन और डेयरी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकीय या परिचालनात्मक सुधारों पर विचार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में डिजिटलीकरण, सतत प्रथाओं और नयाचार को मजबूत करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डेनमार्क, यू.के., चिली, बांग्लादेश, वियतनाम, इज़राइल आदि सहित कई देशों के साथ कई सक्रिय समझौता ज्ञापन/करारों/कार्य समूह/संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सहयोगात्मक प्रयासों का उद्देश्य पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें सीमा पार व्यापार को सुगम बनाने के लिए स्वच्छता उपायों का समन्वय, पशु स्वास्थ्य में सहयोग, पशु चिकित्सा स्वच्छता, उन्नत तकनीकों, आनुवंशिक सुधार, क्षमता निर्माण, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का विकास, सतत मत्स्य प्रबंधन, ज्ञान साझाकरण, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और संयुक्त विकास पहलें शामिल हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग जी20 महामारी निधि के अंतर्गत अनुमोदित "महामारी की तैयारी एवं प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण" नामक परियोजना को भी कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना तीन एजेंसियों अर्थात एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व बैंक और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों/करारों/कार्य समूह/JDI की सूची अनुबंध-I में संलग्न है।

(ख) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के अंतर्गत, पशुपालन राज्य का विषय है जिस पर राज्य विधानमंडल को ही कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है। हालांकि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण, सतत प्रथाओं एवं नवाचार को सुदृढ़ करने के लिए, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने निम्नलिखित उपाय/पहलें की हैं:

i. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): RGM का उद्देश्य देशी नस्लों का विकास और संरक्षण, बोवाइनों की आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइनों के दूध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है।

ii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD): NPDD को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है:

NPDD का **घटक ''क''** गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरण के साथ-साथ राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/ जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ/ स्वयं सहायता समूहों (SHG)/ दुग्ध उत्पादक कंपनियों/ किसान उत्पादक संगठनों के लिए प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढीकरण पर केंद्रित है।

NPDD योजना के **घटक ''ख''** "सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य किसानों की संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाकर, दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता बढ़ाकर दूध और दूध उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

iii. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (SDCFPO) को सहायता: गंभीर प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से उबरने के लिए राज्य डेयरी सहकारी संघों को सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सब्सिडी (नियमित 2% और शीघ्र भुगतान पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके सहायता करना।

iv. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): AHIDF पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण/ सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच प्राप्त होती है।

v. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM): NLM में उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, FPO, SHG, धारा 8 कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन और चारे में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए तथा राज्य सरकार को भी नस्ल सुधार अवसरंचना के लिए सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था है।

vi. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP): पशु रोगों के लिए रोग निरोधी टीकाकरण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए चलाया जा रहा है। इस योजना के

अंतर्गत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ कार्यरत हैं जो द्वार पर जाकर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं।

vii. प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से पूरे देश में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पशु औषधि को LHDCP के तहत जोड़ा गया है।

viii. भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ मिलकर राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM) के अंतर्गत "भारत पशुधन" नामक डेटाबेस विकसित किया है। इस डेटाबेस में प्रत्येक पशु को एक विशिष्ट 12 अंकों की टैग आईडी आवंटित की गयी है और इसमें 36.36 करोड़ पशु पंजीकृत हैं। सभी हितधारक एक ओपन सोर्स एपीआई (API) आधारित आर्किटेक्चर के माध्यम से डेटाबेस से जुड़े हुए हैं।

(ग) पशुधन और डेयरी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा निम्नलिखित तकनीकी या परिचालन पहलें की गई हैं:

i. भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं और सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम (ABIP) लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य लगभग 90% सटीकता के साथ बछड़ियों का उत्पादन करना है, जिससे डेयरी पशुओं की संख्या में वृद्धि हो, नस्ल में सुधार हो और किसानों की आय में वृद्धि हो। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने देशी नस्लों के सेक्स सॉर्टेड सीमन सहित सेक्स सॉर्टेड सीमन को किसानों को उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए देशी सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक का शुभारंभ किया है।

ii. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक का कार्यान्वयन: देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं के प्रजनन हेतु भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 24 IVF प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। यह तकनीक एक ही पीढ़ी में गोपशुओं की आनुवंशिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, किसानों को उचित दरों पर तकनीक उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने देशी IVF मीडिया का शुभारंभ किया है।

iii. जीनोमिक चयन: उच्च आनुवंशिक गुणता (HGM) वाले पशुओं का चयन करने और गोपशुओं और भैंसों के आनुवंशिक सुधार में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने एकीकृत जीनोमिक चिप्स विकसित किए हैं—देशी गायों के लिए गौ चिप और देशी भैंसों के लिए महिष चिप—जो विशेष रूप से देश में उच्च आनुवंशिक गुणता वाले पशुओं के जीनोमिक चयन को शुरू करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

अनुबंध-I

दिनांक 04.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 549 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र. सं.	देश/संगठन	सहयोग का क्षेत्र	हस्ताक्षर करने की तिथि	वैधता
1.	अल्जीरिया	पशु चिकित्सा फील्ड में सहयोग	25 जनवरी, 2001	(सक्रिय)
2.	मोरक्को	पशु चिकित्सा स्वच्छता में सहयोग	27 फरवरी, 2001	(सक्रिय)
3.	चिली	पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग	24 अप्रैल, 2003	(सक्रिय)
4.	मंगोलिया	पशु स्वास्थ्य और डेयरी में सहयोग	17 मई, 2015	(सक्रिय)
5.	डेनमार्क	पशुपालन और डेयरी में सहयोग	16 अप्रैल, 2018	(सक्रिय)
6.	यूनाइटेड किंगडम	पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन में सहयोग	17 अप्रैल, 2018	(सक्रिय)
7.	रूस	कृषि कार्य समूह	29 अगस्त, 2018	(सक्रिय)
8.	यूरोपीय संघ	पशु स्वास्थ्य कार्य समूह	30 मई, 2018	(सक्रिय)
9.	ब्राजील	पशुपालन और डेयरी उत्पादन में सहयोग पर संयुक्त घोषणा	25 जनवरी, 2020	(सक्रिय)
10	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	पशुधन क्षेत्र में सतत सुधार	22 सितम्बर, 2021	(सक्रिय)
11	डेनमार्क	पशुपालन और डेयरी में सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा	2 मई, 2022	(सक्रिय)
12	श्रीलंका	पशुपालन और डेयरी में सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा	21 जुलाई, 2023	(सक्रिय)
13	यूएनडीपी	पशुपालन में टीकों की कोल्ड चेन के प्रबंधन का डिजिटलीकरण और तकनीकी सहायता	20 मई, 2024	(सक्रिय)
14.	नॉर्वे	मत्स्यपालन संबंधी मामलों पर सहयोग	2 मार्च 2010	(सक्रिय)
15.	बांग्लादेश	मत्स्यपालन के फील्ड में सहयोग	22 जून 2024	(सक्रिय)

क्र. सं.	देश/संगठन	सहयोग का क्षेत्र	हस्ताक्षर करने की तिथि	वैधता
16.	आइसलैंड	सतत मत्स्यपालन विकास के क्षेत्र में सहयोग	10 सितम्बर 2019	(सक्रिय)
17.	वियतनाम (dadf)	मत्स्यपालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग	06 जुलाई 2007	(सक्रिय)
18.	मालदीव	समुद्री मत्स्यपालन के फील्ड में सहयोग।	25 जुलाई 2025	(सक्रिय)
19.	अंगोला	मत्स्यपालन, जलीय कृषि और समुद्री संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग	09 नवंबर 2025	(सक्रिय)
20.		इज़राइल राज्य के कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्रालय और भारत गणराज्य के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के बीच मत्स्यपालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त मंत्रिस्तरीय आशय घोषणापत्र।	14 जनवरी 2026	(सक्रिय)

*****